The university has informed that the specifications for offset paper are prescribed on the basis of the advice of the Technical Advisory Committee on paper. The specifications so approved are included in tender documents. The paper purchased by the University during the last three years conformed to the specifications prescribed and none was found to be sub-standard.

(c) to (e) Do not arise.

(f) The Government in the Department of Education has issued no guidelines in this regard.

(g) and (h) Do not arise

Operation blackboard in Maharashtra

3344. SHRI G. PRATHAPA REDDY: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the concrete work done in Maharasthra under the operation blackboard scheme;

(b) how many class-rooms were constructed in Maharashtra under this scheme; and

(c) how much money was spent under this scheme in Maharashtra?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (KUMARI SELJA): (a) Under the scheme of operation Blackboard Teaching Learning Equipment has been sanctioned for all 36800 (100%) primary schools and 1656 (9%) upper primary schools in Maharashtra. 15604 (100%) posts of teachers have been sanctioned for single teacher schools to convert into double teacher schools.

(b) 3152.

(c) A sum of Rs. 125.42 crores has been released to State Govt. of Maharashtra for procurement of Teaching Learning Equipment & appointment of teachers in single teacher schools.

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों हेतु धन एकत्र किया जाना

3345. श्री जे० एस० राजू: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि तीन वर्ष पूर्व पूर्वी दिल्ली और अन्य स्थानों में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा कार्यक्रम आरंभ किए गए थे; यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम कौन-कौन से विद्यालयों में आरंभ किए गए थे;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ प्रशिक्षु छात्रों से कोई मासिक अथवा एकमुश्त शुल्क वसूल किया गया था;

(ग) यदि हां, तो उसका विद्यालय-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त एकमुश्त शुल्क का एक भाग छात्रों को लौटाया जाना था; यदि हां, तो उसका विद्यालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त धनराशि लौटा दी गई है;

(च) क्या इस संबंध में शेष राशि का कोई विवरण उपलब्ध है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(ज) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या रहे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) से (च) भारत सरकार द्वारा पूर्णतया वित्त पोषित "विद्यालयों के लिए संगणक साक्षरता जागरूकता और अध्ययन" (क्लास) नामक परियोजना वर्ष 1984-85 से केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा लागू की जा रही है। तथापि वर्ष 1991-92 में कुछ संगणक फर्मों ने केन्द्रीय विद्यालयों के छात्रों को संगणक शिक्षा प्रदान करने के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन को एक योजना की पेशकश की थी। इस योजना के अंतर्गत छात्रों द्वारा शुल्क का भुगतान किए जाने पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन में प्रायोगिक आधार पर संगणक शिक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव था। मांग का आकलन करने के लिए जिन 10 विद्यालयों में इसे शुरू करने का प्रस्ताव था उसके छात्रों से जनवरी, 1992 में प्रारंभिक विकल्प मांगे गए तथा शुल्क एकत्रित किया गया। तथापि प्रशासनिक कारणों से योजना को मूर्त रूप प्रदान नहीं किया जा सका तथा जून, 1992 में छात्रों से वसूल किए गए शुल्क को वापस करने का आदेश जारी किया गया था। एकत्रित किए गए 20,00,031/-रु. में से 18,49,735/-रु. पहले ही वापस किए जा चुके हैं तथा शेष राशि को वापस करने के संबंध में कार्रवाई जारी है। विद्यालय-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा एकत्र की गई, वापस की गई और वापस की जाने वाली राशि के ब्यौरे

क्रम सं.	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	एकत्र की गई राशि	वापस की गई राशि	वापस की जाने वाली राशि
1.	शालीमार बाग	3,16,483-00	3,16,483-00	शून्य
2.	सेक्टर 8, आर.के.पुरम	2,25,148-00	2,00,427-00	24,721-00
3.	सेक्टर 2, आर.के.पुरम	1,32,555-00	1,29,557-00	2,998-00
4.	सेक्टर 4, आर.के.पुरम	53,427-00	49,512-00	3,915-00
5.	नं. 2, दिल्ली कैण्ट	1,00,713-00	95,613-00	5,100-00
6.	टैगोर गार्डन	4,10,745-00	4,09,445-00	1,300-00
7.	जनकपुरी	2,00,000-00	1,30,915-00	69,085-00
8.	एन्ड्रयूजगंज	2,53,034-00	2,51,060-50	1,973-50
9.	गोल मार्किट	1,50,000-00	1,34,784-75	15,215-25
10.	आई.एन.ए. कालोनी	1,57,926-00	1,31,937-46	25,988-54

Gangsterism in Educational Institutions

3346. SHRI CHIMANBHAI MEHTA:
SHRI G.G. SWELL:
SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the article published in "Hindustan Times" dated 27th July 1994 captioned "Education: Victim of indecision";

(b) if so, what is Government's response to several points raised therein;

(c) whether it is a fact that several universities including Aligarh have been in the throes of gangsterism and appeasement for over two years; and

(d) what steps have been taken to tackle these problems?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (KUMARI SELJA): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) The points raised in the article relate mainly to the alleged shooting and criminalisation of public life in Meerut; delay in appointment of Vice- Chancellor in IGNOU; alleged gangsterism and appeasement in Aligarh Muslim University; and reported reluctance to ensure positive results.

Meerut University is a State University and maintenance of law and order in general is the responsibility of the State Government. As regards alleged gangsterism and appeasement in Aligarh Muslim University, there have been reports of indiscipline on the Campus but to describe that as gangsterism is not correct. There is no appeasement as the District Administration has been helpful in controlling acts of indiscipline on the Campus of the University. As for the appointment of the Vice-Chancellor, IGNOU, the Search Committee appointed to recommend a panel of names has completed its work and a Vice-Chancellor is likely to be appointed shortly.

Bharat Aluminium Company Limited

3347. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Bharat Aluminium Company Limited has signed a Memorandum of Understanding with the Ministry of Mines; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINES (SHRI BALRAM SINGH YADAV): (a) Yes, Sir.

(b) The MOU lays down agreed targets for production, profit, inventory control, consumption of inputs and other efficiency indicators for the Company.